

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व विभाग

देहरादून : दिनांक : 12 जनवरी, 2007

विषय: श्रीमती शशि गोयल पत्नी श्री अनिल मनोहर को दवा उद्योग लगाने हेतु तहसील किच्छा के ग्राम सिरौलीखुर्द में कुल 0.1160 है० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-158/सात-स०भू०अ०/2006 दिनांक 25 नवम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती शशि गोयल पत्नी श्री अनिल मनोहर को दवा उद्योग लगाने हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील किच्छा के ग्राम सिरौलीखुर्द में कुल 0.1160 है० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

- 1- कंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- कंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- कंता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
 - 6- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्तों/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
 - 7- प्रस्तावित कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रचलित नियमों/मानकों एवं उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - 8- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-2005 के अनुरूप निर्माण होगा।
 - 9- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 10- इकाई द्वारा कय की जा रही भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु दवा उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।
 - 11- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 - 12- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 2- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

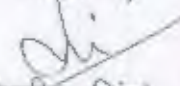
(नृप सिंह नपलच्यल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य राज्य आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- श्रीमती शशि गोयल पत्नी श्री अनिल मनोहर, निवासी-165 गंगापुर बरेली, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सुशील सिंह)
अनु सचिव।